तत्काल जारी करने हेतु

बर्मा: 7 नवंबर के चुनावों को देखते हुए प्रतिबंध सख्त हुए
मिलिट्री पार्टी भावी संसद पर दबदबा बनाने को तैयार

(न्यू यॉर्क, 3 नवंबर, 2010) - ह्यूमन राइट्स वॉच ने आज जारी एक विस्तृत प्रश्नोत्तरी में कहा कि बर्मा की सैनिक सरकार 7 नवंबर, 2010 के निर्धारित चुनावों से पहले आतंक का माहौल बढ़ा रही है जिससे एक नागरिक मुखौटे के साथ सैन्य शासन को जारी रखने की उसकी मंशा जाहिर होती है।
बर्मा के चुनावों पर की प्रश्नोत्तरी चुनाव से संबंधित तकनीकी जानकारियों का वर्णन करती है लेकिन साथ ही यह इस बारे में भी बताती है कि इन चुनावों का बर्मा की आबादी पर क्या असर पड़ेगा और बर्मा में मानवाधिकारों को सुधारने के लिए विदेशी सरकारों को कैसे प्रतिक्रिया करनी चाहिए।

ह्यूमन राइट्स वॉच में एशिया के उप निदेशक, इलेन पियर्सन ने कहा, ‘‘बर्मा के 7 नवंबर के चुनाव डर, आतंक और इस्तीफे के माहौल में संचालित कराए जा रहे हैं। ये चुनाव लोकतांत्रिक संक्रमण के लिए नहीं, बल्कि कुलीन सैन्य परिवर्तन के लिए कराए जा रहे हैं, और इनसे बर्मा में मानवाधिकारों की दयनीय स्थिति में नगण्य बदलाव होगा।‘‘

चुनाव के नजदीक आने के साथ ही, मतदान में अनियमितताओं और सैन्य-समर्थित पार्टियों को वोट देने के लिए प्रलोभन देने की बढ़ती रिपोर्टों के साथ, संपूर्ण बर्मा में मानवाधिकारों की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। सत्ताधारी स्टेट पीस एंड डेवलपमेंट काउंसिल (राजकीय शांति एवं विकास परिषद) ने विदेशी मीडिया पर प्रतिबंधों को सख्त कर दिया है, अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षकों के रहने के सभी प्रस्तावों को खारिज कर दिया है, और अभिव्यक्ति, सभा करने तथा एसोसिएशन की स्वतंत्रताओं पर सख्त नियंत्रण बरकरार रखा है।

इस प्रश्नोत्तरी में चुनाव के लिए निर्मित प्रक्रिया, नई संसद की संभावित बनावट, चुनावों के बाद सेना की भूमिका और चुनावों में भाग ले रही राजनीतिक पार्टियों पर बेहद सावधानी के साथ ध्यान दिया गया है। पंजीकरण का प्रयास करने वाली 47 पार्टियों में से, सैन्य सरकार के संघीय चुनाव आयोग द्वारा 37 को मंजूरी दी गई है। इनमें से अनेक छोटी जातीय पार्टियां हैं जो तीन प्रकार की संसदों के लिए सिर्फ कुछ ही सीटों पर मुकाबला करेंगी। ये तीन प्रकार की संसद हैं: राष्ट्रीय स्तर की पीपुल्स असेम्बली, राष्ट्रीय स्तर की नेशनलिटीज़ असेम्बली, और स्थानीय उम्मीदवारों के लिए 14 क्षेत्रीय संसदें।

वर्ष 2008 के संविधान के तहत, तीनों संसदीय ढांचों में सेवारत सैन्य अधिकारियों के लिए सीटों की काफ़ी बड़ी संख्या आरक्षित होगी। सिर्फ दो पार्टियां ही मुकाबले के लिए खुली रखी गई लगभग प्रत्येक सीट के लिए उम्मीदवार खड़े कर सकेंगी, जो हैं: सैन्य समर्थित यूनियन सोलिडैरिटी एंड डेवलपमेंट पार्टी (यूएसडीपी) और मिलिटरी की पक्षधर भूतपूर्व बर्मीज़ सोशलिस्ट पार्टी, नेशनल यूनिटी पार्टी (एनयूपी)।

चुनावों में अपना दबदबा बनाने को तैयार नजर आती, यूएसडीपी की स्थापना प्रधानमंत्री थिइन सेन और अन्य कैबिनेट मंत्रियों द्वारा की गई थी, और ये सभी अप्रैल माह में सैन्य बलों से इस्तीफा देने वाले सेना के वरिष्ठ अधिकारी रहे हैं। यह पार्टी राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर उम्मीदवारों के लिए खुली रखी गई लगभग सभी सीटों, लगभग 1,158 सीटों, के लिए उम्मीदवार खड़े करेगी।

इससे पहले इस वर्ष में, यूएसडीपी ने वर्ष 1993 में बनी, मिलिटरी द्वारा निर्मित और नियंत्रित यूनियन सॉलिडैरिटी एंड डेवलपमेंट एसोसिएशन (यूएसडीए) की वित्तीय परिसंपत्तियों, विस्तृत बुनियादी ढांचे और सदस्यता सूची के बहुसंख्यक, लगभग 18 लाख लोगों, को अपने में शामिल कर लिया था। यूएसडीए और इसके संसदीय अंग लंबे समय तक विपक्ष के खिलाफ हिंसक हमले करने में संलिप्त रहे हैं, और पिछले कुछ वर्षों से चुनावों की तैयारी में स्थानीय विकास परियोजनाओं का सेहरा अपने सिर पर बांधते रहे हैं। स्थानीय समुदायों और छोटी पार्टियों ने चुनावों के नजदीक आने के साथ ही यूएसडीपी के पार्टी सदस्यों द्वारा, अक्सर स्थानीय सुरक्षा बलों के साथ मिलकर, आतंक फैलाने और प्रलोभन देने की घटनाओं में बढ़ोत्तरी होने की सूचना दी है।
पियर्सन ने कहा, ‘‘यूएसडीपी मुट्ठी भर छोटे विपक्षी दलों को किनारे लगाने वाला सिर्फ एक विशाल आतंककारी निकाय ही नहीं है, बल्कि यह सेना के प्रभुत्व को जारी रखने की सुनिश्चितता प्रदान करने के लिए सोच-समझकर बनाया गया एक सत्तावादी राजनीतिक ढांचा भी है।’’

‘‘सैन्य शासन को एक नागरिक शक्ल प्रदान करने के लिए, आतंक और भ्रष्टाचार के घृणित कार्यों के जरिए, यूएसडीपी पूरे बर्मा में फैल गया है।‘‘

राजनीतिक विपक्ष से संबंध रखने वाली कुछ पार्टियों ने सेना से जुड़ी दो मुख्य पार्टियों के खिलाफ एक गठजोड़ बनाया है, जिसमें नज़रबंद की गई लोकतांत्रिक नेता आंग सान सू की की पार्टी के कुछ भूतपूर्व सदस्यों द्वारा गठित नेशनल डेमोक्रेटिक फोर्स, नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, और यूनियन डेमोक्रेटिक पार्टी शामिल है। ये पार्टियां साथ मिलकर सिर्फ कुछ ही उम्मीदवार खड़े कर सकती हैं।

प्रश्नोत्तरी चुनावों के प्रति अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की प्रतिक्रिया को भी संबोधित करती है और बताती है कि बर्मा में वास्तविक परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए सरकारों को क्या करना चाहिए। पक्षपातपूर्ण चुनावी प्रक्रिया की व्यापक अंतर्राष्ट्रीय आलोचना के बावजूद बर्मा की सैन्य सरकार के कानों में जूं तक नहीं रेंगी। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव बान की-मून ने प्रगति की इस कमी को "हताशापूर्ण" कहा, और अमेरिकी विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन ने चुनावों को "बेहद विसंगतिपूर्ण" बताया। भारतीय और चीनी अधिकारियों ने बर्मा की चुनाव प्रक्रिया के लिए समर्थन जताया है।

प्रश्नोत्तरी में, ह्यूमन राइट्स वॉच ने सरोकार रखने वाली सरकारों से विविध कदम उठाने का आग्रह किया है, जिसमें सभी राजनीतिक कैदियों की तत्काल और बिना शर्त रिहाई करने का आह्वान करना, और नई सरकार पर मानवाधिकारों का सम्मान करने और चुनावों को सर्वसमावेशी राजनीतिक प्रक्रिया बनाने के लिए दबाव डालना शामिल है। इसके अतिरिक्त, सरकारों को मानवीयता रखने वाली एजेंसियों और मीडिया की ज्यादा से ज्यादा पहुंच बनाने, और बर्मा के नागरिक समाज तथा विकास समूहों पर लगे अत्यधिक प्रतिबंधों को हटाने के लिए दबाव डालना चाहिए।

पियर्सन ने कहा, ''अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को यह जानने के लिए 7 नवंबर तक प्रतीक्षा करने की जरूरत नहीं है कि ये चुनाव ऊपर से लेकर नीचे तक अन्यायपूर्ण हैं।'' ''सरकारों और यूएन को बर्मा में वास्तविक परिवर्तन के लिए नई सरकार पर दबाब डालने हेतु सख्त कदम तय करने के लिए एकसाथ मिल कर काम करना चाहिए।"